

संपादकीय

उत्तराखण्ड हाई कोर्ट का फैसला - कि अतिक्रमित भूमि पर रखने की वजह से किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता - भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को बोहरता है। वोटिंग का अधिकार संविधान की ओर से दिया गया है और इसका आधार जमीन का टुकड़ा नहीं हो सकता। न यह अधिकार नकारा करना कामज़ार है कि इसे किसी सरकारी फरमान से छीना जा सके। उत्तराखण्ड के उद्घम सिंह नगर जिले के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में इसे वापस नहीं ले सकता। राज्य सरकार का यह

याचिका दायर कर राज्य सरकार के उस आदेश को बुनाई दी थी, जिसमें कहा गया था कि सरकारी, जंगल या किसी और जमीन पर अतिक्रमण करके रहने वालों को पंचायत चुनावों में मतदान करने या इलेक्शन लड़ने से वंचित किया जाएगा। हाई कोर्ट ने इस पर साक किया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मताधिकार सुरक्षित है और न्यायालिका या सरकार कोई भी इसे वापस नहीं ले सकता। राज्य सरकार का यह

आदेश अगर लागू हो जाता, तो एक खतरनाक मिसाल बन सकता था। देश के कई हिस्सों में आज भी लाखों लोग ऐसी जमीनों पर रह रहे हैं, जिनका स्वामित्व स्पष्ट नहीं है, खासगौर पर शहरों के बीच बसी झुग्गियों, गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में। देश में वैसे ही जमीनें से जुड़े मुकदमे बरसों तक चलने के लिए बदनाम हैं। कई ड्राफ्ट आर्टिकल का शामिल किया जा रहा था, तब भी इस पर आपत्ति उठाई गई थी। एक सदर्यने वे द्वारा मताधिकार का विरोध करते हुए अंदेशा जाताया था कि अगर मतदाता जागरूक

इनके संविधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाए। लोकतंत्र में मताधिकार के लिए बुनाई प्रक्रिया का एक अंग नहीं है। इसी से भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। संविधान ने देश के लोगों को यह अधिकार दिया है जब अनुच्छेद 326 के ड्राफ्ट आर्टिकल का शामिल किया जा रहा था, तब भी इस पर आपत्ति उठाई गई थी। एक सदर्यने वे द्वारा मताधिकार का विरोध करते हुए अंदेशा जाताया था कि अगर मतदाता जागरूक

और शिक्षित न हुआ, तो संसदीय लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि बढ़ ने इस अंदेशों को हाय में उड़ा दिया। हर नागरिक, जो निर्वाचित आय पूरी कर चुका हो और कुछ विशेष आधारों पर अयोग्य न हो, उसे मतदाता बनने का अधिकार है। शुरुआत में यह आयु 21 वर्षीय, जिसे 6 12 संविधान संशोधन के जरिये घटाकर 18 वर्ष किया गया। इसका मतदातव जिद्द के देश का अपने लोगों पर योकीन और पक्का हुआ। जमीन से जुड़े द्वारा दिया गया को लेकर इस योकीन को तोड़ा नहीं जा सकता। हां, अतिक्रमण बड़ी समस्या है, पर उससे निपटने का तरीका बह नहीं, जो उत्तराखण्ड सरकार ने खो जा।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं मुक्त दुनिया को निर्मित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने, कार्यावाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गलत सूचनाओं का मुकाबला करना और नशीली दवाओं के बारे में तथ्यों को साझा करना है। साथ ही साक्ष्य आधारित रोकथाम, स्वास्थ्य जोखिमों और विश्व नशीली दवाओं की समस्या, उपचार और देखभाल से निपटने के लिए उपलब्ध समाधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अवैध ड्रग्स एवं तस्करी मानव के लिए बहुत बड़ी पीड़ि

एवं संकट का स्रोत है। सबसे कमज़ोर लोग, खास तौर पर युवाओं, इस संकट का खामियाजा भुगतते हैं।

नशीली दवाओं के खिलाफ महत्वाकांक्षी युद्ध का आह्वान

(लिलित गर्ग)

भारत में नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है, जो भौगोलिक रूप से कमज़ोर, बहुत उपलब्ध और कम उम्मीदों से प्रेरित है। यह समस्या सभी आयु समूहों में फैली हुई है, लेकिन युवाओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं मुक्त दुनिया को निर्मित करने के लक्ष्य को प्राप्त करना और सहयोग को मजबूत करने के लिए उपलब्ध समाधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसका उद्देश्य गलत सूचनाओं का मुकाबला करना और नशीली दवाओं के बारे में तथ्यों को साझा करना है। अवैध ड्रग्स एवं तस्करी मानव के लिए बहुत बड़ी पीड़ि

एवं संकट का स्रोत है। सबसे कमज़ोर लोग, खास तौर पर युवाओं, इस संकट का खामियाजा भुगतते हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले सभी की जान रोकते हैं। इसके अलावा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे के खिलाफ आजीविका सहित रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है, जो भौगोलिक रूप से कमज़ोर, बहुत उपलब्ध और कम उम्मीदों से प्रेरित है। यह समस्या सभी आयु समूहों में फैली हुई है, लेकिन युवाओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है, जो भौगोलिक रूप से कमज़ोर, बहुत उपलब्ध और कम उम्मीदों से प्रेरित है। यह समस्या सभी आयु समूहों में फैली हुई है, लेकिन युवाओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे के खिलाफ आजीविका सहित रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है, जो भौगोलिक रूप से कमज़ोर, बहुत उपलब्ध और कम उम्मीदों से प्रेरित है। यह समस्या सभी आयु समूहों में फैली हुई है, लेकिन युवाओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे के खिलाफ आजीविका सहित रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है, जो भौगोलिक रूप से कमज़ोर, बहुत उपलब्ध और कम उम्मीदों से प्रेरित है। यह समस्या सभी आयु समूहों में फैली हुई है, लेकिन युवाओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे के खिलाफ आजीविका सहित रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है, जो भौगोलिक रूप से कमज़ोर, बहुत उपलब्ध और कम उम्मीदों से प्रेरित है। यह समस्या सभी आयु समूहों में फैली हुई है, लेकिन युवाओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे के खिलाफ आजीविका सहित रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है, जो भौगोलिक रूप से कमज़ोर, बहुत उपलब्ध और कम उम्मीदों से प्रेरित है। यह समस्या सभी आयु समूहों में फैली हुई है, लेकिन युवाओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे के खिलाफ आजीविका सहित रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है, जो भौगोलिक रूप से कमज़ोर, बहुत उपलब्ध और कम उम्मीदों से प्रेरित है। यह समस्या सभी आयु समूहों में फैली हुई है, लेकिन युवाओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे के खिलाफ आजीविका सहित रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है, जो भौगोलिक रूप से कमज़ोर, बहुत उपलब्ध और कम उम्मीदों से प्रेरित है। यह समस्या सभी आयु समूहों में फैली हुई है, लेकिन युवाओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे के खिलाफ आजीविका सहित रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है, जो भौगोलिक रूप से कमज़ोर, बहुत उपलब्ध और कम उम्मीदों से प्रेरित है। यह समस्या सभी आयु समूहों में फैली हुई है, लेकिन युवाओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे के खिलाफ आजीविका सहित रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है, जो भौगोलिक रूप से कमज़ोर, बहुत उपलब्ध और कम उम्मीदों से प्रेरित है। यह समस्या सभी आयु समूहों में फैली हुई है, लेकिन युवाओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण है

धर्म स्तंभ काउंसिल व निर्वाणी अखाड़ा ने मुख्यमंत्री से की माँग-सभी जिलों में मठ-मंदिर एवं सार्वजनिक न्यास मामलों के लिए बने अलग समर्पित कार्यालय

तीन लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति प्रदेश के मठ मंदिरों और न्यास में :डॉ निर्वाणी

बेमेतरा/मूक पत्रिका



धर्म स्तंभ काउंसिल एवं निर्वाणी अखाड़ा के डॉ. सौभग्य निर्वाणी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पैट कर छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में मठ-मंदिर, सार्वजनिक न्यास एवं ट्रस्ट से जुड़े मामलों के लिए जिला कलेक्टर के अधीन अलग से तीन समर्पित कर्मचारियों के स्थायी कार्यालय की माँग की। डॉ. सौभग्य निर्वाणी ने कहा कि, «आज ज्ञानी स्तर पर देखा गया है कि जिला कलेक्टर जो स्वयं सार्वजनिक न्यासों के संबंधों होते हैं, वे अपनी कार्यों का हस्तांतरण अनुवर्णायां अधिकारीयों (गोपन) को कर देते हैं। किंतु राजस्व अधिकारीयों के पास पहले से ही जुड़े संलग्नों में भीष्म और राजस्व कार्यालय के नाम पर कलेक्टर में जमा रही है।» जिन और संपत्तियों में लूट की स्थिति, कोइ निश्चयनी नहीं है।

धर्म स्तंभ काउंसिल ने यह भी चेताया कि—जन आस्था के कारण जिले में फिलो भूमि और वाता/अल अधिकारीयों में लगातार अनियन्त्रित बंदर बांद हो रहा है, और इस पर रोक लगाने वाली संथाएँ या तंत्र लगभग नियक हैं। इसकी पुष्टिमित्र में अवश्यक है कि हर जिले में कलेक्टर के अधीन मठ-मंदिर एवं ट्रस्ट मामलों के लिए समर्पित

अनुभवी व समेतनशील कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, जो इन मामलों के गंभीर पूर्वांक देखें।

लोट डोमेन में आए ट्रस्टों की जानकारी-धर्म स्तंभ काउंसिल और अखाड़ा ने वह भी माँग रखी कि सार्वजनिक न्यासों, मठ-मंदिर ट्रस्टों की संपत्तियों, आय और जननित में किए गए कार्यों की जानकारी परिलेक डोमेन में नियमित रूप से अलांड़े की जाए। इसके लिए नई कार्यालयों बनाने की आवश्यकता बताई गई है।

डॉ. सौभग्य निर्वाणी ने बताया कि इस दिनों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सार्वजनिक और सकारात्मक चर्चा हुई है और योग्य से हुई दिनों में सकारात्मक रूप पर ठेस नियन्त्रण लिए जाने की उम्मीद है।

वर्षे से नहीं हुए चुनाव, विभाग उदासीन-धर्म स्तंभ काउंसिल ने इस गंभीर विषय पर भी ध्यान दिलाया कि, «प्रदेश में कई ट्रस्ट एवं सार्वजनिक न्यास ऐसे हैं, जिनमें वापर से चुनाव ही नहीं हुआ है, न विभाग ने इस पर कोई वित्त दिलाया है, न उनका कोई दिलचस्पी दिखायी है। इससे पारदर्शिता और जन विश्वास पर गहरा आतंक हुआ है।»

*धर्म स्तंभ काउंसिल ने अपनी माँग में मध्य प्रदेश सार्वजनिक न्यास अनियन्त्रित, 1951 (जो वर्तमान में छोड़ा गया है) तथा भारतीय सर्वविद्वान की धर्मिक

स्वतंत्रता एवं आस्थास्क संपत्ति के संबंध से जुड़ी धाराओं का भी हलात दिया।

प्रमुख माँग विषयों में: 1. प्रलेक जिले में कलेक्टर के अधीन 3 समर्पित कर्मचारी नियुक्त किए जाएं, जो केवल मठ-मंदिर एवं ट्रस्ट मामलों को देखें।

2. जन आस्था से प्राप्त संपत्तियों पर हो रहे अनियन्त्रित बैंकोंवारे पर गेक के लिए नियरानी ढांचा बने।

3. ट्रस्टों की संपत्तियाँ, आय और जननित कार्यों की विपरीट सार्वजनिक की जाए।

4. सभी ट्रस्टों में सम्य-सम्य पर चुनाव सुनिश्चित कराए जाएं।

5. सार्वजनिक न्यास अधिनियम को संसदी से लापू करने हेतु विशेष दिशा-निर्देश जारी हों।

धर्म स्तंभ काउंसिल के इस माँग पर गमजानकी मंत्रियों में लगातार अनियन्त्रित बंदर बांद हो रहा है, और इस पर रोक लगाने वाली संथाएँ या तंत्र लगभग नियक हैं। इसकी पुष्टिमित्र में अवश्यक है कि हर जिले में कलेक्टर के अधीन मठ-मंदिर एवं ट्रस्ट मामलों के लिए समर्पित

ग्राम कातलबोड की बदहाल गली बना अमृतकाल का 'कड़वा सच, तीन पंचर्षीय बीते, विकास आज भी दूर की कौड़ी



बाद भी यहां विकास की रफ्तार अब तक नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जपातानिधियों और अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उत्थाया गया।

यह गली बरसात के दिनों में इतनी बदहाल हो जाती है कि बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है और बुजुर्जों के लिए घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं होता। सरकार जहां एक ओर +विकसित भारत + और +अमृत काल+ का गलियां जबाब मांग रही हैं।

सपने दिखा रही है, वहां दूसरी ओर कातलबोड जैसे गांव इन दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह गांव आज भी बुनियादी सुविधा - समुचित सड़क मार्ग - से वैचित है। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस गली का पक्का नियांगी कार्य शुरू हो ताकि उन्हें इस नारकीय स्थिति से राहत मिल सके। क्या +अमृत काल+ का यही चेहरा है? कातलबोड की गलियां जबाब मांग

जगदलपुर नगर निगम के सभापति संग्राम सिंह राणा को समकालीन सूत्र की प्रति विजय सिंह ने भेट की

विजय सिंह की रचनाएँ बस्तर के जनजीवन से उठती हैं-संग्राम सिंह



जगदलपुर/मूक पत्रिका

विजय सिंह 4 दशकों से रोग कर्म व साहित्य साधना के चिरते कर्म के रूप में उभर कर सामने आए हैं। रविवार के समकालीन सूत्र की प्रति भेट की गई विजय सिंह का साहित्य पूरे देश में जाना जाता है उनकी रचनाएँ प्राकृतिक पहाड़ों जंगलों कि उस परिभाषा में गढ़ते हैं जो बस्तर के सहज जीवन को समाने लगाता है। मूल्यों के बाहक और प्राकृतिक चिरताओं के कारण उन्हें अपनी जाती है जो जगदलपुर शहर से प्रकाशित बस्तर की उस मारी से जानीजीवन शब्दों से प्रस्तुत होता है। विजय सिंह की कार्य रचना बस्तर की बोलती मारी के शब्द है।

मूल्यों के बाहक और प्राकृतिक चिरताओं में पर्यावरण का स्पष्ट चिंतन दिखाई पड़ता है। उनकी रचनाएँ में बस्तर का विजय सिंह सहज जीवन को समाने लगातार योग्य होता है। विजय सिंह की कार्य रचना बस्तर की बोलती मारी की प्रतीक रही है। विजय सिंह की कार्य रचना बस्तर की बोलती मारी के शब्द है।

विधायक दीपेश साहू भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हुए शामिल

सनातन परंपरा को सशक्त करता यह भव्य मंदिर - विधायक दीपेश साहू



बेमेतरा/मूक पत्रिका

बेमेतरा विधायक सभा क्षेत्र के ग्राम रेवेली में बोले शनिवार को नवनिर्मित भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं समस्त क्षेत्र की सुख-सुमुद्रित एवं उत्तमता की कामना की।

उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी समाज के संबोधित करते हुए कहा कि बैंक एवं श्रद्धा भाव के साथ नवाचार करने के लिए यह एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी समाज के संबोधित करते हुए करेंगे। यह एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी समाज के संबोधित करते हुए करेंगे। यह एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी समाज के संबोधित करते हुए करेंगे।

पहुंचकर भक्त माता कर्मा की प्रतिमा

के समक्ष पुष्प अर्पित कर पूजा-अर्चना की तथा समस्त क्षेत्र की सुख-सुमुद्रित एवं उत्तमता की कामना की।

उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक एवं श्रद्धा भाव के साथ नवाचार करने के लिए यह एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी समाज के संबोधित करते हुए करेंगे।

प्रति सजगता, स्वदेशी को बढ़ावा, और अन्य अवधारणाएँ एवं पर्यावरण का लिए यह एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी समाज के संबोधित करते हुए करेंगे।

सांसद महेश कश्यप ने कहा कि बैंक एवं श्रद्धा भाव के साथ नवाचार करने के लिए यह एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी समाज के संबोधित करते हुए करेंगे।

प्रति सजगता, स्वदेशी को बढ़ावा, और अन्य अवधारणाएँ एवं पर्यावरण का लिए यह एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी समाज के संबोधित करते हुए करेंगे।

प्रति सजगता, स्वदेशी को बढ़ावा, और अन्य अवधारणाएँ एवं पर्यावरण का लिए यह एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी समाज के संबोधित करते हुए करेंगे।

प्रति सजगता, स्वदेशी को बढ़ावा, और अन्य अवधारणाएँ एवं पर्यावरण का लिए यह एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी समाज के संबोधित करते हुए करेंगे।

प्रति सजगता, स्वदेशी को बढ़ावा, और अन्य अवधारणाएँ एवं पर्यावरण का लिए यह एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी समाज के संबोधित करते हुए करेंगे।

प्रति सजगता, स्वदेशी को बढ़ावा, और अन्य अ